

## मानवाधिकार आयोग ने किशोर संग पुलिसकर्मियों के गैंग रेप पर बैठाई जांच

**लखनऊ (एसएनबी)।** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरदोई पुलिस कर्मियों द्वारा एक किशोर के साथ गैंग रेप की घटना की शिकायत का संज्ञान लेते हुए जांच कराने के आदेश दिये हैं व संबंधित एक्शन रिपोर्ट चार सप्ताह के अंदर तलब किया है। मानवाधिकार आयोग ने यह कार्यवाही लखनऊ की स्वयंसेवी संस्था भ्रष्टाचार अन्वेषण एवं उन्मूलन परिषद के चेयरमैन एके त्रिपाठी की शिकायत का संज्ञान लेते हुए की है। मानवाधिकार आयोग ने शिकायत की प्रति पुलिस महानिदेशक को भेजते हुए घटना को गंभीर माना है। आयोग ने हरदोई जिले के बाहर के किसी सीनियर रैंक पुलिस अधिकारी (एसपी रैंक से नीचे नहीं) से पूरे मामले की जांच करा जरूरी एक्शन लेने के निर्देश दिये हैं। जांच रिपोर्ट व कार्यवाही से संबंधित रिपोर्ट भी चार सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने के आदेश किये गये हैं। मानवाधिकार आयोग में की गई शिकायत के अनुसार हरदोई को कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने अपने 13 वर्षीय बेटे के साथ क्राइम ब्रांच के पुलिस कर्मियों पर कोतवाली के अंदर कुकर्म करने का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की थी। महिला ने आरोपी दो युवकों व क्राइम ब्रांच के पुलिस कर्मियों पर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की थी। एसपी ने जांच सीओ का सौंपी थी। घटनाक्रम के अनुसार क्राइम ब्रांच की टीम लड़के को जीडीसी स्कूल तिराहे से पृछताछ के लिए पकड़कर ले गई थी।

## **NHRC to meet stakeholders to discuss medical education, doctors rights UDFA seeks suggestions**

<https://www.edexlive.com/news/2024/Apr/15/nhrc-to-meet-stakeholders-to-discuss-medical-education-doctors-rights-udfa-seeks-suggestions>

The meeting is scheduled for April 24, 2024, at Manav Adhikar Bhawan, INA, Delhi. The meeting will be presided over by Justice Arun Mishra, Chairperson of the NHRC

The National Human Rights Commission (NHRC) has invited stakeholders for a core committee meeting on April 24 to discuss the current issues and challenges related to the rights of patients and doctors in India. Concerning the same, the National President of the United Doctors Front Association (UDFA) Dr Lakshya Mittal is seeking suggestions from doctors on topics which could be discussed in the meeting.

According to the document EdexLive has access to, "The meeting is scheduled for April 24, 2024, at Manav Adhikar Bhawan, INA, Delhi. The meeting will be presided over by Justice Shri Arun Mishra, Chairperson of the NHRC." The document was issued by NHRC to UDFA's Dr Lakshya Mittal on April 9.

Further, it said that the following agendas will be discussed during the four technical sessions:

1. Issue of bonds in medical education
2. Patients' rights
3. Doctors' rights
4. Problems in disbursal of stipends to interns and PG students.

"The objective of this important meeting is to derive specific actionable points that can be further implemented," the document read. Speaking to EdexLive, Mittal said, "NHRC has taken an outstanding step. I am hopeful for a positive outcome as a former judge of the Supreme Court, who is the current NHRC chairperson, will be heading the meeting."

# अरशद की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त

संवाददाता, जागरण • भागलपुर : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वृहद आश्रय स्थल में रखे गए मु. अरशद की 25 दिसंबर 2023 को रहस्यमय परिस्थिति में हुई मौत मामले का संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 13 फरवरी 2024 को अरशद की रहस्यमय परिस्थिति में हुई मौत मामले में केस दर्ज किया गया था। आयोग ने उस मामले में भागलपुर पूर्वी क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक से अरशद की मौत को लेकर अद्यतन पुलिस रिपोर्ट मांगी है। यह रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आयोग अपना निर्णय देगा। आश्रय स्थल में मारपीट होने पर अरशद के गंभीर रूप से जखमी हो जाने पर इलाज के लिए उसे जवाहर लाल नेहरू मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 25 दिसंबर 2023 को वहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया था।

14 दिसंबर 2024 को आश्रय स्थल में पियूष से हुई थी मारपीट: वृहद आश्रय

**25** दिसंबर 2023 को जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में उपचार के दौरान हुई थी मौत

वृहद आश्रय स्थल में अमन कुमार के साथ अरशद की हुई थी मारपीट उसे जखमी हालत में कराया गया था अस्पताल में भर्ती

स्थल में आवासित अरशद से किसी बात को लेकर आश्रय स्थल में ही आवासित पियूष कुमार से पहले कहासुनी हुई थी। उस दौरान हुई कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई थी। तब उसे जखमी हालत में आनन-फानन में जवाहर लाल नेहरू मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस दौरान समाज कल्याण निदेशालय के निदेशक को जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक ने रिपोर्ट भेजकर जानकारी दी थी कि आश्रय स्थल में अरशद की पियूष के साथ कहा सुनी होने



के बाद पियूष ने अरशद को धक्का दे दिया था। मामले की समीक्षा के बाद जिलाधिकारी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रिपोर्ट भेज यह जानकारी दी थी कि आश्रय स्थल में आवासित दोनों किशोरों में हुई मारपीट में चोट लगने से अरशद की मौत हो गई थी। जिलाधिकारी ने 27 दिसंबर 2023 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश से इस मामले की न्यायिक जांच कराने का अनुरोध किया था। गंभीर चोट के बाद भी बेहतर उपचार के लिए नहीं ले जाया गया था बाहर: अरशद की मौत के बाद यह सवाल

तब तेजी से सुखी बनी थी कि 14 दिसंबर 2023 की रात मारपीट में गंभीर रूप से जखमी होने पर भी अरशद को बेहतर इलाज के लिए बाहर नहीं ले जाया गया था। जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। वहीं उपचार के दौरान 25 दिसंबर को उसकी मौत हो गई थी। यानी जब उसे गंभीर चोट लगी थी, जखम गहरा था तो दस दिनों तक जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में रखने के बजाय बेहतर उपचार के लिए उसे पटना या अन्य बेहतर अस्पताल में उसका उपचार कराया जाना था। लेकिन दस दिनों तक जवाहर लाल नेहरू मेडिकल अस्पताल में ही रखा गया। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अरशद की मौत मामले में लापरवाही समेत अन्य बिंदुओं को गंभीरता से लिया है। अब पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन बाद आयोग में आगे की कार्रवाई होनी है।

## State issues dengue SOP, sanctions 3.5cr for clean-up

<https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/state-issues-dengue-sop-sanctions-3-5cr-for-clean-up/articleshow/109327056.cms>

Kolkata: The state urban development agency (SUDA) has issued an SOP, sanctioning Rs 3.5 crore and additional manpower to conduct a one-time cleaning drive at govt establishments from April 29 to June 1 to minimise potential mosquito-breeding conditions. Across the state, 129 civic bodies, including BMC and NKDA, have been covered under this.

“This is the first time that this drive will be taken up. Civic workers will be trained on vector-borne disease control measures. The civic bodies will take up the cleaning drive with state govt funding and assistance. The one-time cleaning drive will cover all urban local bodies, govt health and educational institutions, all govt housing estates, state govt offices and ICDS centres. Core team members shall be assigned specific wards to monitor the cleaning on a regular basis. The dates of cleaning will be scheduled in coordination with the institutions concerned,” said an official.

We also published the following articles recently

Who will clean polluted Yamuna? In Mathura, river cleaning big poll issue  
In Mathura, political candidates pledge to restore the polluted Yamuna river amidst local demand for action. The issue gains significance as Hema Malini, Narendra Dhangar, and Suresh Singh promise to address industrial waste, sewage, and local sentiments.109267448

NHRC issues notice to Maha govt, DGP over death of 4 workers during sewage cleaning  
NHRC notice sent to Maharashtra govt over workers' death cleaning sewage treatment plant in Mumbai without gear, highlighting toxic gas suffocation, negligence, and state authorities' duty.109275108

Sea of issues in Pondy, none to clean up  
V Vaithilingam and A Namassivayam vie for Puducherry's solitary parliamentary seat amid financial struggles and statehood aspirations. AIADMK's G Tamizhvendan and NTK's R Menaga join the electoral fray, adding to the political complexity in the Union territory.109266548

# नाबालिग किरणी बिरहोर की मौत पर आयोग ने लिया संज्ञान

रांची. हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड की पगार बिरहोर टोला निवासी नाबालिग किरणी बिरहोर की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है. इस मामले में आयोग ने हजारीबाग डीसी को आठ सप्ताह में कार्रवाई प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया है.

मामले में शनिकांत ने आयोग से शिकायत की थी. कहा था कि चट्टी बरियातू कोल परियोजना से महज कुछ दूरी पर लुप्तप्रायः आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय की एक बस्ती है, जहां पर खनन कार्य किया

- मौत मामले में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया
- हजारीबाग डीसी को आठ सप्ताह में रिपोर्ट दायर करने का निर्देश

जा रहा है. इसके दुष्प्रभाव से नाबालिग किरणी बिरहोर बीमार चल रही थी. इसी दौरान 28 फरवरी को उसकी मौत हो गयी. इसको लेकर आयोग से बिरहोर बस्ती को बिना बसाये खनन कार्य करने और किरणी बिरहोर की मौत के जिम्मेदार लोगों को चिह्नित कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गयी थी.

## Climate of terror: Human rights body reveals report on Sandeshkhali violence

<https://www.msn.com/en-in/news/India/climate-of-terror-human-rights-body-reveals-report-on-sandeshkhali-violence/ar-BB1IzkY8?ocid=StaticFallback>

The National Human Rights Commission (NHRC) on Saturday flagged several human rights concerns in its enquiry report over the allegations of sexual harassment raised by the women of West Bengal's Sandeshkhali.

The rights body said that the villagers of Sandeshkhali "faced assault, threats, sexual exploitation, land grabbing, and forced unpaid labour" and a "climate of terror" was created by officials who have been alleged to have worked in connivance with the accused.

The NHRC said its enquiry has revealed several instances of atrocities inflicted upon the victims, which "clearly demonstrate, prima facie, that there was a violation of human rights due to negligence in the prevention of such violation or abatement thereof by the public servant".

At the centre of the women's allegations was suspended Trinamool Congress leader Sheikh Shahjahan and his aides. The women spoke up after he went into hiding before his arrest.

The atrocities committed by the accused "rendered the victims silent and intimidated" and the subsequent terror "created reluctance to seek justice" said the NHRC. The residents of Sandeshkhali were forced to seek a livelihood elsewhere due to the situation, it added.

The rights body also pointed out that there are allegations of discrimination/denial of benefits of state/central government schemes by officials in collusion with the accused. It said a climate of terror was created by the fear of reprisal, the power dynamics at play.

It is an urgent need to create a safe and supportive environment for the victims to "break free from the shackles of silence" and to ensure the cycle of abuse no longer exists, said NHRC.

The atmosphere of fear not only affects the victims but also has a negative impact on the growth and health of the children who witness the ordeals of their parents at the hands of the accused, it added.

"The NHRC investigation team found that there is a need to uproot the fear of these people from the hearts of the victims to enable them to live their normal lives with their families and gain the confidence to live in society with dignity and pride," said the report.

The report further stated that it is the duty of the district authorities to take measures to instil confidence in the residents of the area in general and victims in particular, so that people may come forward and file their complaints

#### NHRC'S RECOMMENDATIONS TO BENGAL GOVERNMENT:Â

Reinstating trust in the rule of law and confidence in authorities.

Ensuring witness protection and redressal of grievances.

Counseling and rehabilitation of victims of sexual offences.

Return of the land to the legitimate owners.

Impartial investigation of complaints by central agencies.

Initiating awareness programmes.

Operationalisation of Nationwide Emergency Response System (NERS).

Vocational training and creating employment opportunities.

Reviving the land to make it suitable for agriculture.

Improving socioeconomic indicators and preparing area-specific plans.

Appointing Special Rapporteurs to periodically report on the situation in Sandeshkhali.

Investigation of cases of missing women/girls from the area ofÂ Sandeshkhali Police Station.

The NHRC had taken suo motu cognisance of the allegations being raised by the women in the village in February.Â The human rights body has sent its enquiry report to the Chief Secretary and West Bengal DGP (police).

It has also sought an Action Taken Report from the Chief Secretary within the next eight weeks.

**मानवाधिकार  
आयोग ने  
किशोर संग  
पुलिसकर्मियों  
के गैंग रेप पर  
बैठाई जांच**

**लखनऊ (एसएनबी)**। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरदोई पुलिस कर्मियों द्वारा एक किशोर के साथ गैंग रेप की घटना की शिकायत का संज्ञान लेते हुए जांच कराने के आदेश दिये हैं व संबंधित एक्शन रिपोर्ट चार सप्ताह के अंदर तलब किया है। मानवाधिकार आयोग ने यह कार्यवाही लखनऊ की स्वयंसेवी संस्था भ्रष्टाचार अन्वेषण एवं उन्मूलन परिषद के चेयरमैन एके त्रिपाठी की शिकायत का संज्ञान लेते हुए की है।

मानवाधिकार आयोग ने शिकायत की प्रति पुलिस महानिदेशक को भेजते हुए घटना को गंभीर माना है। आयोग ने हरदोई जिले के बाहर के किसी सॉनियर रैंक पुलिस अधिकारी (एसपी रैंक से नीचे नहीं) से पूरे

**घटना को गंभीर माना  
चार सप्ताह में रिपोर्ट तलब**

मामले की जांच करा जरूरी एक्शन लेने के निर्देश दिये हैं। जांच रिपोर्ट व कार्यवाही से संबंधित रिपोर्ट भी चार सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने के आदेश किये गये हैं। मानवाधिकार आयोग में की गई शिकायत के अनुसार हरदोई को कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने अपने 13 वर्षीय बेटे के साथ क्राइम ब्रांच के पुलिस कर्मियों पर कोतवाली के अंदर कुकर्म करने का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की थी। महिला ने आरोपी दो युवकों व क्राइम ब्रांच के पुलिस कर्मियों पर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की थी। एसपी ने जांच सीओ का सौंपी थी। घटनाक्रम के अनुसार क्राइम ब्रांच की टीम लड़के को जोड़ीसी स्कूल तिराहे से पृछताछ के लिए पकड़कर ले गई थी।



## **Sandeshkhali victims faced sexual exploitation: NHRC**

<https://hindupost.in/crime/sandeshkhali-victims-faced-sexual-exploitation-nhrc/#>

National Human Rights Commission (NHRC) of India in its spot enquiry report reveals that the victims (villagers of Sandeshkhali in West Bengal) 'faced assault, threat, sexual exploitation, land grabbing, and forced unpaid labour' and hence many residents were compelled to seek livelihood outside their locality. The NHRC report, released on 13 April 2024 in New Delhi, also stated that the atmosphere due to the atrocities by the alleged accused persons rendered the victims silent and reluctant to seek justice.

It revealed several instances of atrocities inflicted upon the victims, which clearly demonstrate, prima facie, that there was a violation of human rights due to negligence in the prevention of such violation or abatement thereof by the public servant. The report has been duly sent to the chief secretary and police chief of West Bengal 'for submitting an action taken report within eight weeks on each of the recommendations' and the NHRC has uploaded the enquiry report on its website for wider dissemination of information.

Mentionable is that the NHRC had taken suo motu cognizance of print & electronic media outlets on 21 February, where many innocent and impoverished women were reported having harassed and sexually assaulted by a group of political persons in Sandeshkhali under North 24 Paragana, because of which many local villagers started protesting for appropriate legal action against the perpetrators of horrific crimes 'indulged by various goons and anti-social elements', where the concerned administration failed to take appropriate legal actions. Considering the gravity of the situation, the NHRC deputed an investigation team for a spot enquiry in addition to calling for reports from the State government in Kolkata.

The concerned West Bengal authorities informed that altogether 25 cases were registered (among which 7 cases were on alleged complaints of sexual offence against women) and 24 accused persons were arrested. Efforts continued to arrest all the absconding perpetrators of the crime. However, the NHRC investigation team found that there is a need to uproot the fear of those criminals from the hearts of victims so that they can return to their normal lives along with their families and gain the confidence to live with dignity and pride. It asserted that it's the duty of district authorities to take consistent measures to instil confidence in all the residents in general and victims in particular so that others, who have been victims of crimes, may come forward and file their complaints seeking justice.

## Meeting for selection of NHRC chairperson and members to be held on May 31

<https://ca.style.yahoo.com/style/meeting-selection-nhrc-chairperson-members-044038542.html>

By Amit Kumar

New Delhi [India], May 26 (ANI): A meeting of the committee for the selection of chairperson and members of the National Human Rights Commission of India (NHRC) will be held on May 31 at 7 Lok Kalyan Marg, as per the official sources on Wednesday. Prime Minister Narendra Modi will chair the meeting.

Government sources told ANI, "A meeting of the committee for selection of chairperson and member of NHRC has been called on May 31 at 7 Lok Kalyan Marg. PM Narendra Modi will chair the meeting."

Sources further told ANI that the committee for the selection of NHRC chairperson and other members includes the Prime Minister, Union Home Minister, Lok Sabha Speaker, Deputy Chairman Rajya Sabha, and Opposition leader of Rajya Sabha.

The post of NHRC chairperson has been vacant since Justice HL Dattu, a former Chief Justice of India, completed his tenure on December 2, 2020.

Justice Prafulla Chandra Pant, a former Judge of the Supreme Court of India, is currently serving as acting chairperson of the NHRC. (ANI)

## **NHRC to meet stakeholders to discuss medical education, doctors' rights; UDFA seeks suggestions**

<https://www.msn.com/en-in/health/medical/nhrc-to-meet-stakeholders-to-discuss-medical-education-doctors-rights-udfa-seeks-suggestions/ar-BB1DfeF>

The National Human Rights Commission (NHRC) has invited stakeholders for a core committee meeting on April 24 to discuss the current issues and challenges related to the rights of patients and doctors in India. Concerning the same, the National President of the United Doctors Front Association (UDFA) Dr Lakshya Mittal is seeking suggestions from doctors on topics which could be discussed in the meeting. According to the document EdexLive has access to, "The meeting is scheduled for April 24, 2024, at Manav Adhikar Bhawan, INA, Delhi. The meeting will be presided over by Justice Shri Arun Mishra, Chairperson of the NHRC." The document was issued by NHRC to UDFA's Dr Lakshya Mittal on April 9.

Further, it said that the following agendas will be discussed during the four technical sessions:

1. Issue of bonds in medical education
2. Patients' rights
3. Doctors' rights
4. Problems in disbursement of stipends to interns and PG students.

"The objective of this important meeting is to derive specific actionable points that can be further implemented," the document read. Speaking to EdexLive, Mittal said, "NHRC has taken an outstanding step. I am hopeful for a positive outcome as a former judge of the Supreme Court, who is the current NHRC chairperson, will be heading the meeting."

## हजारीबाग की नाबालिग किरणी बिरहोर की मौत पर आयोग ने लिया संज्ञान

<https://www.prabhatkhabar.com/state/jharkhand/hazaribagh/hazaribagh-and-jharkhand-news-56>

हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड की पगार बिरहोर टोला निवासी नाबालिग किरणी बिरहोर की मौत मामले में **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है.

हजारीबाग की नाबालिग किरणी बिरहोर की मौत पर आयोग ने लिया संज्ञानहजारीबाग डीसी को आठ सप्ताह में रिपोर्ट दायर करने का निर्देश

रांची. हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड की पगार बिरहोर टोला निवासी नाबालिग किरणी बिरहोर की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है. इस मामले में आयोग ने हजारीबाग डीसी को आठ सप्ताह में कार्रवाई प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया है. मामले में शनिकांत ने आयोग से शिकायत की थी. कहा था कि चट्टी बरियातू कोल परियोजना से महज कुछ दूरी पर लुप्तप्रायः आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय की एक बस्ती है, जहां पर खनन कार्य किया जा रहा है. इसके दुष्प्रभाव से नाबालिग किरणी बिरहोर बीमार चल रही थी. इसी दौरान 28 फरवरी को उसकी मौत हो गयी. इसको लेकर आयोग से बिरहोर बस्ती को बिना बसाये खनन कार्य करने और किरणी बिरहोर की मौत के जिम्मेदार लोगों को चिह्नित कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गयी थी.

## **Sandeshkhali: SC grants two weeks to LS to respond to plea of West Bengal chief secretary, others**

<https://www.newindianexpress.com/nation/2024/Apr/15/sandeshkhali-sc-grants-two-weeks-to-ls-to-respond-to-plea-of-west-bengal-chief-secretary-others>

On February 19, the top court stayed the notices issued by the privileges committee to the West Bengal chief secretary, director general of police (DGP) and others.

NEW DELHI: The Supreme Court on Monday granted two weeks to the Lok Sabha Secretariat and others to file their replies to a plea moved by top bureaucrats from West Bengal against their summoning by the privileges committee of the Lower House of Parliament.

They were summoned by the Committee of Privileges of the Lok Sabha over a complaint of "misconduct" filed against them by Bharatiya Janata Party (BJP) MP Sukanta Majumdar when he was trying to visit violence-hit Sandeshkhali, a village in North 24 Parganas district of the state.

On February 19, the top court stayed the notices issued by the privileges committee to the West Bengal chief secretary, director general of police (DGP) and others.

Majumdar was hospitalised following clashes between BJP workers and police personnel after the workers of the saffron party were stopped from visiting Sandeshkhali.

Chief Secretary Bhagwati Prasad Gopalika, the then Director General of Police (DGP) Rajeev Kumar and others, including the district magistrate and superintendent of police of North 24 Parganas, were summoned to appear before the privileges committee of the Lok Sabha at 10:30 am on February 19.

A bench comprising Chief Justice D Y Chandrachud and justices J B Pardiwala and Manoj Misra took note of the submissions made by Solicitor General Tushar Mehta, representing the Lok Sabha Secretariat (Privileges and Ethics Branch), and senior advocates Abhishek Singhvi and Gopal Sankaranarayanan, who appeared in the court on behalf of the state officials, and posted the plea for hearing after two weeks.

"The parties shall file a brief note, not exceeding five pages, on or before two weeks and the matter will be listed exactly after two weeks," the CJI said. Singhvi told the court that the privileges committee of the Lok Sabha has never acted so fast and moreover, there was "no breach by any iota of imagination".

The court ordered on February 19 that "there shall be a stay of further proceedings in pursuance of the Office Memorandum dated February 15...issued to the petitioners".

While staying the notices issued to the state officials, the bench had listed the plea for hearing on March 22.

The CJI's bench had taken the pleas moved by the West Bengal officials as the first matter on an urgent mentioning by the senior officials.

The lawyer representing the Lok Sabha Secretariat had opposed the grant of stay by the court, saying this was the first sitting of the privileges committee.

"They are not being accused of anything. This is a regular process. Once an MP sends a notice and the speaker thinks there is something to look into, notices are issued," the counsel had said, adding that this was the "threshold stage".

Besides the Lok Sabha Secretariat, the Committee of Privileges of the Lok Sabha, Majumdar, the Department of Personnel and Training (DoPT) and the Ministry of Home Affairs are the respondents to the petition filed by the state officials.

Majumdar and others were stopped from entering Sandeshkhali, where women were agitating over alleged atrocities committed against them by Trinamool Congress leader Shajahan Sheikh and his aides.

Several women in the region have accused Sheikh and his supporters of land-grab and sexually assaulting them under coercion.

Sheikh, who was on the run, was subsequently arrested.